शिक्षक पोर्टल एवं नवाचार समूह
मध्यप्रदेश

दसवीं-बारहवीं को लेकर आज हो सकता है फैसला, स्कूल शिक्षा मंत्री ने बुलाई बैठक

हरिभूमि न्यूज ⏭ भोपाल

प्रदेश में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच एक माह के लिए स्थगित हुई माध्यमिक शिक्षा मंडल की कक्षा दसवीं-बारहवीं की बोर्ड परीक्षाओं को लेकर फैसला सोमवार को हो सकता है।

इसको लेकर स्कूल शिक्षा मंत्री इंदरसिंह परमार ने दोपहर बाद अफसरों की बैठक बुलाई है। विभागीय सूत्रों की मानें तो सरकार 12वीं की परीक्षाएं जून माह में कराने पर विचार कर रही है, इसको लेकर तैयारियां भी लगभग पूरी हो चुकी हैं। हालांकि परीक्षा ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन इस पर अंतिम मुहर इस बैठक में लगेगी। इसके साथ ही 10वीं की परीक्षा ऑनलाइन होंगी या आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर रिजल्ट घोषित होगा, इसे लेकर भी बैठक में विचार-विमर्श किया जाएगा।

असमंजस में विद्यार्थी और अभिभावक

एमपी बोर्ड 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं को लेकर आज हो सकता है फैसला

स्टार समाचार | भोपाल

माध्यमिक शिक्षा मंडल (माशिमं) की दसवीं और बारहवीं की परीक्षाओं को लेकर कोई निश्चित फैसला नहीं होने कारण अभिभावक, शिक्षक व बच्चों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। दोनों की कक्षाओं में पूरी तरह जनरल प्रमोशन नहीं दिया जाएगा। सोमवार को इसको लेकर स्कूल शिक्षा राज्यमंत्री इंदरसिंह परमार की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की जाएगी। इसमें आंतरिक मूल्यांकन या ऑनलाइन कक्षाओं को लेकर विचार-विमर्श किया जाएगा। हालांकि स्कूल शिक्षा मंत्री ने पहले ही स्पष्ट किया था कि जनरल प्रमोशन किसी भी हाल में नहीं देंगे।

स्कूल शिक्षा विभाग ने कोरोना के बढ़ते प्रकरणों के मद्देनजर 30 अप्रैल की बजाय जून के पहले सप्ताह से आयोजित करने का फैसला तो ले लिया है, लेकिन यह परीक्षाएं किस पद्धति से होंगी, अभी तक यह तय नहीं हो पाया है। सीबीएसई ने दसवीं की परीक्षा को रद्द कर आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर मूल्यांकन करने के आदेश दिए हैं। अब प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के देखते हुए स्कूल शिक्षा विभाग मप्र बोर्ड की कक्षा दसवीं और बारहवीं की परीक्षाओं के आयोजन को लेकर मंथन कर रहा है, लेकिन अब तक कोई निर्णय नहीं हो सका है। ऐसे में कोरोना संक्रमण बढ़ने के साथ-साथ अभिभावकों और विद्यार्थियों को परीक्षा की चिंता सताने लगी है।

जून तक स्थगित की थी परीक्षा

अधिकारियों ने बताया कि दसवीं में आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर मूल्यांकन और बारहवीं में ऑनलाइन पेपर देकर ओपन बुक पैटर्न पर कराने पर अंतिम फैसला लिया जाना है, लेकिन अभी इस बात पर भी असमंजस है कि दसवीं के आंतरिक मूल्यांकन के लिए परीक्षाएं या टेस्ट लिए गए हैं या नहीं। ज्ञात हो कि प्रदेश में कक्षा एक से आठवीं तक के स्कूल पहले ही बंद हैं। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए नौवीं से बारहवीं तक की वार्षिक व प्री-बोर्ड परीक्षाएं भी बंद कर दी गई है। वहीं पहले के परीक्षा कार्यक्रम में दसवीं की परीक्षा 30 अप्रैल से बारहवीं की परीक्षाएं एक मई से आयोजित होनी थी। उन्हें जून तक के लिए स्थगित कर दिया गया है।

ऑनलाइन कक्षाओं में नई पाठ्य सामग्री का अभाव

भोपाल(नवदुनिया प्रतिनिधि)। कोरोना महामारी के कारण पहली से आठवीं कक्षा के स्कूल इस सत्र में भी खुल नहीं पाएं। वहीं प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में 13 जून तक ग्रीष्मावकाश घोषित कर दिया गया है।

पिछले सत्र की तरह इस साल भी स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से पहली से आठवीं कक्षा के बच्चों लिए रेडियो व दूरदर्शन के माध्यम से पढ़ाई कराई जा रही है। एक अप्रैल से राज्य शिक्षा केंद्र की ओर से रेडियो व दूरदर्शन पर नए सत्र का शुभारंभ कर दिया गया है, लेकिन पाठ्य सामग्री पुरानी होने से बच्चे रुचि नहीं ले रहे हैं। विभाग की ओर से रेडियो व टीवी पर नई पाठ्य सामग्री तैयार नहीं की गई है। इस कारण पढ़ाई नीरस हो रही है। राज्य शिक्षा केंद्र के मीडिया प्रभारी अमिताभ अग्रवाल ने बताया कि 30 अप्रैल तक पिछले सत्र के पाठ्यक्रम को प्रसारित किया जाएगा। इसके बाद नई सामग्री को तैयार किया जाएगा। अभी कोरोना के कारण नए कार्यक्रम तैयार नहीं हो पाए हैं। उल्लेखनीय है कि शैक्षणिक गतिविधियां रेडियो पर सुबह 10 से 11 बजे और शाम पांच से 5.30 बजे तक एवं दूरदर्शन पर दोपहर 12 बजे से 1.30 बजे तक संचालित की जा रही हैं। रेडियो पर सुबह पहली से आठवीं के लिए पाठ्यपुस्तक आधारित हिंदी, गणित, अंग्रेजी विषयों में और शाम को खेल, योग, कला, म्यूजिक पढ़ाया जाता है।

शासकीय कर्मचारी अपने 1 दिन का वेतन सरकार के आपदा कोष में जमा करेंगे

भोपाल (आरएनएन)। मध्यप्रदेश की धरती पर कोरोना वायरस के अदृश्य संक्रमण से संघर्ष करती राज्य सरकार के साथ शासकीय कर्मचारी सहयोग देने के लिए आगे आए हैं। कर्मचारियों ने अपने 1 दिन का वेतन इस संकट की घड़ी में शासकीय आपदा कोष में जमा करने का निर्णय लिया है। इस संबंध में राज्य कर्मचारी संघ ने वर्चुअल बैठक कर प्रदेश के समस्त पदाधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ का कहना है कि संभागबार जिला एवं प्रदेश पदाधिकारियों की वर्चुअल बैठक करके पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं के परिवार की स्वास्थ्य की जानकारी के साथ.साथ कोरोना से लड़ाई हेतु प्रेरित किया जा रहा है। अनेक साथी और परिवार के सदस्य बीमार है एवं दिवंगत साथियों के लिए सामूहिक प्रार्थना कर संबल प्रदान कर रहा है। प्रदेश के महामंत्री हेमंत श्रीवास्तव ने बताया कि वर्तमान में प्रदेश के कर्मचारी लगातार सरकार के सहयोग में कार्य कर रहे हैं। जिसमें अनेक कर्मचारी कोरोना के संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। संगठन के लोग लगातार संपर्क करके परिवार को कोरोना के प्रति जागरुकता और संबल प्रदान कर रहे हैं। इंदौर सागर जबलपुर संभाग की बैठक हो चुकी है। साथ ही अन्य संभागों की बैठक प्रतिदिन जारी है। मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ ने कोरोना की इस त्रासदी में सहयोग के लिए अपना 1 दिन का वेतन मुख्यमंत्री सहायता कोष में देने का निर्णय लिया है। बैठक में राष्ट्रीय महामंत्री विष्णु वर्मा प्रदेश अध्यक्ष विश्वजीत सिंह सिसोदिया प्रदेश कोषाध्यक्ष अनिल एडविन प्रदेश संगठन मंत्री अनिल भार्गव कार्यालय मंत्री सुरेंद्र सिंह सहित संभाग में निवासरत प्रदेश पदाधिकारी और जिले के अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष इस वर्चुअल बैठक में सहभागिता ले रहे हैं।

राज्य कर्मचारी संघ ने वर्चुअल बैठक कर लिया निर्णय

संघर्ष समिति ने किया एक दिन का वेतन देने का आव्हान

इधर मध्य प्रदेश जागरूक अधिकारी कर्मचारी संयुक्त समिति ने प्रदेश के शासकीय सेवकों से आव्हान किया है कि आपदा की इस घड़ी में अपने 1 दिन का वेतन आर्थिक कोष में जमा करें। समिति के संयोजक प्रमोद तिवारी ने बताया कि इस संदर्भ में प्रदेश के समस्त जिला अध्यक्ष को पत्र लिखा गया है।

पत्र में आग्रह किया है कि इस संकट के समय सभी को एकजुट होकर सरकार का सहयोग करना है। ताकि हम कंधे से कंधा मिलाकर महामारी संक्रमण से लड़ सके। उन्होंने बताया है कि प्रदेश के समस्त कर्मचारी संवर्ग को मानवीय आधार पर अपने 1 दिन का वेतन सरकार के आपदा कोष में जमा करना चाहिए। क्योंकि इस समय सरकार को प्रत्येक व्यक्ति के सहयोग की आवश्यकता है।

एंकर स्टोरी

शिक्षकों को कोराना योद्धा घोषित करने और इलाज के लिए आर्थिक मदद की मांग की

प्रदेश में 334 शिक्षकों की कोरोना से मौत, 1633 हुए संक्रमित

शहर प्रतिनिधि, भोपाल। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं। कोई भी विभाग कोरोना के कहर से अछूता नहीं है। प्रदेश का स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारी, कर्मचारी, प्राचार्य और शिक्षकों को संख्या भी बढ़ती जा रही है। अभी प्रदेश में विभाग के अधिकारी, कर्मचारी व शिक्षक सहित 366 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। इसमें सबसे ज्यादा 334 शिक्षकों की संख्या है। साथ ही 19 कर्मचारी, 11 प्राचार्य और 2 अधिकारी शामिल हैं। वहीं कोरोना संक्रमितों में भी 1809 में से 1633 शिक्षक कोरोना संक्रमित हैं। साथ ही 80 प्राचार्य, 73 कर्मचारी व 23 अधिकारी शामिल है। प्रदेश भर में कोरोना से मौत और संक्रमितों में शिक्षकों की संख्या अधिक है। इसका कारण यह है कि शिक्षकों को कोरोना आपदा सेंटर, कोरोना सर्वे और टीकाकरण कार्य में ड्यूटी लगाई गई है। वहीं शिक्षक संगठनों ने विरोध जताते हुए मांग की है कि शिक्षकों को कोरोना योद्धा घोषित किया जाए। उनके इलाज में अतिरिक्त मदद की जाए। इस संबंध में मध्यप्रदेश शिक्षक कांग्रेस के प्रांतीय प्रवक्ता सुभाष सक्सेना ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि वर्तमान में कोरोना महामारी का भयावह स्थिति है । इस स्थिति में प्रदेश के हजारों नियमित शिक्षक एवं अध्यापक संवर्ग के शिक्षक संक्रमित हो गए हैं। इससे सैकड़ों शिक्षक व अध्यापक मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं। वर्तमान में कोरोना का इलाज बहुत महंगा हो गया है। इसकी दवाइयां इंजेक्शन, ऑक्सीजन इत्यादि बहुत महंगे दामों में मिल रहे हैं। ऐसे में शिक्षकों को इलाज कराने के लिए अतिरिक्त संकट खड़ा हो गया है। इसके निराकरण के लिए हमारी मांग है कि प्रदेश में जो नियमित शिक्षक है उनके भविष्य निधि खाते से 24 घंटे के अंदर दो लाख रुपये निकालने के निर्देश दिए जाए एवं अध्यापकों को 24 घंटे के अंदर निकलना एडवांस के रूप में दो लाख रुपये उनके खाते में दिए जाए और उस राशि को आसान किस्तों में वापस ले लिया जाए।

इन जिलों में सबसे अधिक शिक्षक संक्रमित

जिला	संक्रमित	शिक्षक	मौत	शिक्षक
भोपाल	259	235	10	8
इंदौर	180	164	9	7
उज्जैन	110	100	51	51
सिंगरौली	106	103	35	33
शिवपुरी	135	129	27	24
बालाघाट	86	82	9	9
होशंगाबाद	90	77	9	8
सागर	39	32	29	27
सिवनी	38	38	8	8
राजगढ़	51	43	4	5
नरसिंहपुर	51	42	7	7

भोपाल में सबसे अधिक शिक्षक संक्रमित

भोपाल जिले में सबसे अधिक 235 शिक्षक संक्रमित हैं। वहीं आठ शिक्षकों की कोरोना से मौत हुई है। वहीं उज्जैन में 110 संक्रमितों में से 51 शिक्षकों की मौत हुई है।

कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय अधिक सुदृढ़ होंगे

स्कूल शिक्षा विभाग ने जारी किया 5.50 करोड़ का बजट

शहर संवाददाता, भोपाल। अब प्रदेश के 275 कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय अधिक सुदृढ़ होंगे। इसके लिए आवासीय विद्यालयों के लिए राशि दी गई है। जिससे कोरोना काल के बाद जब स्कूल खुलेंगे तो बालिकाओं को आदर्श विद्यालय में पढ़ने का मौका मिलेगा। समग्र शिक्षा अभियान के तहत स्कूल शिक्षा विभाग ने प्रत्येक कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय को तीन लाख रुपये के हिसाब से राशि वितरित की है। विभाग की ओर से आवासीय विद्यालयों में फर्नीचर से लेकर मूलभूत सुविधाओं को ठीक करने के लिए सवा पांच करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। इसके लिए विद्यालयों से जिन संसाधनों की कमी थी, उसकी पूरी रिपोर्ट मांगी गई थी। ज्ञात हो कि इन विद्यालयों में 75 फीसदी अनुसूचित जाति, जनजाति, आर्थिक पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक समुदाय की बालिकाओं और 25 फीसद गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवार की बच्चियों का दाखिला होता है। प्रत्येक आवासीय विद्यालयों में 150 से 300 तक सीटें रहती हैं।

मूलभूत सुविधाओं को सुदृढ़ किया जाएगा: विभाग के पास शिकायत मिली थी कि आवासीय विद्यालयों में मूलभूत सुविधाओं की कमी है। कई आवासीय विद्यालयों में चारदीवारी नहीं है तो कुछ में स्वच्छ शौचालय की कमी है। वहीं कुछ में बिजली और फर्नीचर कमी है। इसे सुदृढ़ करने के लिए विभाग ने बजट स्वीकृत किए हैं। साथ ही इसे जल्द से जल्द सुधारने के आदेश दिए हैं।

जब 10 फीसदी उपस्थिति के निर्देश तो कैसे बुला सकते हैं सभी कर्मचारियों को

भोपाल (आरएनएन)। महामारी संक्रमण से बचाव को लेकर एक और राज्य सरकार ने समस्त सरकारी कार्यालयों में मात्र 10 प्रतिशत उपस्थिति निर्धारित की है। वही भोपाल संभाग आयुक्त कार्यालय में प्रतिदिन शत प्रतिशत कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जा रही है। कमिश्नर कार्यालय की इस व्यवस्था के विरोध में सरकारी कर्मचारी खड़े हो गए हैं। मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष जितेनद सिंह ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा है कि राज्य मंत्रालय और सतपुड़ा से लेकर विंध्यांचल सहित संभाग जिला एवं ब्लॉक कार्यालय तक 10 फ़ीसदी उपस्थिति राज्य सरकार द्वारा अनिवार्य की गई है। उसके बाद भी संभागीय कार्यालय में प्रतिदिन कर्मचारियों की शत.प्रतिशत मौजूदगी दर्ज करवाई जा रही है। कर्मचारी संघ अध्यक्ष का आरोप है कि जो सेवक ड्यूटी करने नहीं पहुंच रहा है उसको कार्यवाही का भय दिखाया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि कार्यालय के कई कर्मचारी संक्रमित हो चुके हैं। फिर भीआदेश के अनुसार यहां ड्यूटी नहीं लगाई जा रही है।

अनुग्रह राशि के लिए तरस रहे शिक्षकों के परिजनः आरोप

पीसं,जबलपुर। कोरोना के कारण जिले में दर्जनों शिक्षक अपनी जान गंवा चुके हैं। सामान्यतः शासन द्वारा मृत कर्मचारियों के आश्रित परिवार के सदस्य को तत्काल अनुग्रह राशि रू 50,000/-देकर राहत दी जाती है। वहीं मृत शिक्षकों के परिजन इस राशि के लिए भटक रहे हैं।इस संबंध में मप्र तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ ने बताया कि परिजन अस्पतालों के भारी भरकम बिल तथा अंतिम संस्कार में जमा पूंजी खर्च कर चुके हैं।

गौरतलब है कि विकास खण्ड के उपेन्द्र कुमार यादव, मो. एहसान खान, अनीता गिडियन, ए लाकरा, विनोद कुमार जैन, गणेश सारथी, आशालता मसीह, किशोर ठाकुर, किशन लाल मरावी, सदा शिवराज खोपडे, राजेश मार्को, जितेन्द्र सिंह ठाकुर, प्रियंका खरे, हरप्रसाद ठाकुर, अनिलबह पलमेंका, राजू पाण्डे, बबीता गुप्ता शहीद हो चुके हैं। संघ के योगेन्द्र दुबे, अर्वेन्द्र राजपूत, अवधेश तिवारी, गोविन्द विल्थरे, अटल उपाध्याय, आलोक अग्निहोत्री, मुकेश सिंह, दुर्गेश पाण्डे, बृजेश मिश्रा, डी.डी.गुप्ता, रजनीश तिवारी, पवन श्रीवास्तव, अमित नामदेव, सुधीर खरे, राजेश गुर्जर, बृजेश ठाकुर, नितिन श्रृंगी, जितेन्द्र त्रिपाठी आदि ने कलेक्टर से मृतकों के परिजनों को शीघ्र अनुग्रह राशि के भुगतान की मांग की है।

कोरोना काल: स्कूल शिक्षा विभाग ने एक बार फिर वर्ग एक और वर्ग दो के अंग्रेजी-गणित पढ़ाने शिक्षकों से आवेदन मांगे

गणित-अंग्रेजी के शिक्षकों का टोटा, अतिथि के भरोसे शिक्षा

पत्रिका न्यूज नेटवर्क

patrika.com

भोपाल. प्रदेश की स्कूली शिक्षा अतिथि शिक्षकों के सहारे चल रही है। कोरोना की वजह से सरकार नए शिक्षकों की भर्ती नहीं कर पा रही। 31 हजार से ज्यादा अतिथि शिक्षक ऑनलाइन पढ़ाई की डोर को थामे हुए हैं। सरकार के पास आठवीं से बारहवीं तक के छात्रों को पढ़ाने के लिए गणित और अंग्रेजी के शिक्षक नहीं हैं। सरकार इन अतिथि शिक्षकों के सहारे ही गणित और अंग्रेजी की पढ़ाई करवा रही है। विभाग ने एक बार फिर वर्ग एक और दो के अंग्रेजी और गणित पढ़ाने आवेदन मांगे हैं।

शिक्षकों की कमी की पूर्ति कर रहे हैं लेकिन कोरोना के कारण प्रक्रिया रुकी हुई है। स्थिति सुधरते ही नए शिक्षकों की भर्ती की जाएगी।

इंदर सिह परमार,
स्कूल शिक्षा मंत्री

31559 अतिथि शिक्षक
20835 वर्ग एक
10722 वर्ग दो
02 शिक्षक मिडिल स्कूल में
7330 स्कूलों में कार्यरत
4219 हाई स्कूल और हायर सेकंडरी स्कूलों में सेवाएं
766583 पंजीकृत आवेदक स्कूल शिक्षा विभाग में अतिथि शिक्षकों के
396463 सत्यापित आवेदक

(शिक्षा सत्र 2020-21 के अनुसार स्थिति)

आवेदन आमंत्रित

विभाग ने नए शिक्षण सत्र के लिए अतिथि शिक्षकों के आवेदन ऑनलाइन आमंत्रित किए हैं। आवेदन सीनियर सेकंडरी स्कूलों में अंग्रेजी और गणित विषय के लिए हैं।

22 हजार पदों पर भर्ती की प्रक्रिया

प्रदेश के पांच हजार से ज्यादा स्कूल शिक्षक विहीन हैं। कहीं एक तो कहीं दो शिक्षको के सहारे स्कूल हैं। सरकार करीब 22 हजार शिक्षकों की भर्ती कर रही है। स्कूल मर्ज भी किए जा रहे हैं।

अभिकरण गठन की कवायद शुरू

भोपाल @ पत्रिका. निजी स्कूलों के शिक्षकों की समस्याओं को दूर करने सरकार राज्य स्तर पर ट्रिब्यूनल बनाने जा रही है। स्कूल शिक्षा विभाग ने गठन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अभिकरण को न्यायिक अधिकार होंगे। शिक्षकों को स्कूल से निकालना, वेतन कटौती, स्कूल में प्रताड़ना या अतिरिक्त काम कराने जैसी समस्याओं को न सिर्फ सुनेगा, बल्कि उन्हें दूर भी करेगा।

प्रदेश के निजी स्कूलों में तीन लाख से ज्यादा शिक्षक हैं। कम वेतन, ज्यादा काम और बिना किसी कारण नौकरी से निकालने जैसी समस्याओं से अक्सर दो-चार होना पड़ना है। वे कोर्ट जाते हैं, लेकिन लंबा समय बीत जाता है और समझौता करने पर मजबूर हो जाते हैं। हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में इस तरह की याचिका भी दायर की गई थी। जवाब में सरकार ने अभिकरण गठन की बात कही है। गठन जिला मजिस्ट्रेट की देखरेख में किया जा सकता है। अभिकरण के गठन का मसौदा तैयार किया जा रहा है। कोरोना के बिगड़ते हालातों के कारण समय सीमा कुछ कम-ज्यादा हो सकती है।

दैनिक भास्कर दतिया 25-04-2021

शिक्षक संघ ने अभियान चलाकर को बांटे मास्क, किया जागरूक

भास्कर संवाददाता | मुरैना

कोरोना संक्रमण के बीच मप्र शिक्षक संघ के पदाधिकारियों ने शनिवार को शहर में कोविड-19 संक्रमण से बचाव को लेकर अभियान चलाया। अभियान के दौरान शिक्षकों ने उचित सामाजिक दूरी बनाए रखने का संदेश दिया। इसके अलावा जरूरतमंदों को मास्क वितरित किए। संघ के जिला अध्यक्ष नरेश सिकरवार ने कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए बसों से यात्रा कर रहे व सड़कों के किनारे रहने वाले घुमक्कड़ जाति के लोगों को कोरोना बचाव के तरीके समझाए। झोपड़ियों में रहने वाले मजदूरों को मास्क वितरित कर उसका सही इस्तेमाल करना बताया। जिलाध्यक्ष सिकरवार ने कहा कि कोरोना वायरस का कहर दुनियाभर में कम नहीं हो पा रहा है। पूरी दुनिया में कोरोना के केस कम हो रहे है वही भारत में कोरोना के नियम का पालन न करने से लाखों नए मरीज इसकी चपेट में आ रहे हैं। इससे बचने का सिर्फ एक उपाय है वैक्सीनेशन और कोविड अनुरूप व्यवहार। इसके लिए मास्क सबसे जरूरी है । कोरोना होने पर घबराए नहीं डॉक्टर से सलाह लें। सुरक्षा उपायों से कोरोना को मात दे सकते हैं। गैर जरूरी होने पर घर से न निकलें। कोरोना वायरस अब बच्चो को भी बीमार कर रहा है। उन्होंने अभिभावकों से अपील की कि बच्चों को कोरोना से बचाव के उपाय का पालन करने के बारे में समझाएं। अभियान में विमलेश यादव, सतंजय मिश्रा, रघुराज परमार, रामावतार सिकरवार, महेश गुप्ता, प्रदीप दंडोतिया व जगदीश शर्मा आदि शामिल रहे।

एक-एक स्कूल में दो-दो सरप्लस किसी जिम्मेदार ने कलम नहीं चलाई

कामचलाऊ डीईओ रहते टीपी सिंह ने किया था कमाल, केएस कुशवाहा चले गए क्या सच्चिदानंद लेंगे सुध

पैसे की हनक थी या फिर कायदों से खिलवाड़ की आदत? दोनों ही अनुत्तरित प्रश्न है लेकिन २ साल पहले जो हुआ उसका खामियाजा सरकार भुगत रही है। मामला शिक्षकों की पोस्टिंग का था। यहां कामचलाऊ डीईओ रहे एक सहायक संचालक ने एक एक स्कूल में दो-दो सरप्लस कर गए। ऐसा होने पर एक बाबू को बलि का बकरा बना दिया गया। अब जब दो जिम्मेदार बदल गए पर सुध नहीं ली।

सतना, एमपीजेएस न्यूज

कामचलाऊ डीईओ रहे टीपी सिंह ने अपने बीते कार्यकाल में एक और कमाल किया। जहां शिफ्टिंग के नाम पर स्कूटर पर अलमारियों का परिवहन कराया वहीं शिक्षकों के ट्रांसफर में अपनों के साथ-साथ सुविधा शुल्क देने वालों को उपकृत कर दिया। इन ट्रांसफरों में माननीयों की अनुशंसों को भी रद्दी की टोकरी में डाल दिया। जबकि अपने एक शिक्षक रिश्तेदार की सिफारिशों को खूब तवज्जो दी।

कार्यालय से जुड़े सूत्रों पर भरोसा करें तो नवंबर-दिसम्बर २०१९ में स्कूल शिक्षा विभाग की एक गाइडलाइन आई थी जिसमें अतिशेष शिक्षकों का प्रशासकीय ट्रांसफर किया जाना था। इस ट्रांसफर को आनलाइन के माध्यम से किया जाना था। कामचलाऊ डीईओ टीपी सिंह ने आनलाइन ट्रांसफर तो किया लेकिन आंख मूंद ली। आंख ऐसी मूंदी कि जहां बच्चे नहीं थी उन स्कूलों में शिक्षक भेज दिए। यही नहीं जिस विद्यालय में अतिशेष मानकर शिक्षकों को हटाया वहीं दूसरे विद्यालय का शिक्षक पोस्टेड कर दिया। मिसाल के तौर पर कुलगढ़ी संकुल के प्राथमिक शाला ककरहा में पदस्थ शिक्षक जितेन्द्र सिंह को अतिशेष बताकर कोटरहाई भेजा गया। इनकी जगह मढ़ई की शिक्षिका रीना द्विवेदी को ककरहा ट्रांसफर कर दिया। ये दोनों ही ऑर्डर २५ नवम्बर २०१९ को किए गए थे। मामला यहीं नहीं रूका अतिशेष के नाम पर ट्रांसफर किए गए दो दर्जन से भी अधिक शिक्षक न्यायालय की शरण में चले गए वहां से उनके ट्रांसफर ऑर्डर पर स्थगन दे दिया गया। इस तरह से जो दूसरे विद्यालय से आया वह भी उसी विद्यालय में पदस्थ हो गया। इस तरह से एक अतिशेष हटाने के ना पर दो दो अतिशेष बना दिए गए।

5 दर्जन मामलों पर कोर्ट केस

डीईओ रहते हुए कलेक्टर चैंबर जैसा अपना चैंबर बनाने का शौक पालने वाले तरुणेन्द्र प्रताप सिंह ने स्कूल शिक्षा विभाग सहित सतना जिला के विधायक, सांसद और अन्य जनप्रतिनिधियों की अनुशंसाओं को रद्दी की टोकरी में डालने का दुस्साहस किया ही इसके अलावा न्यायालयीन मामले भी बना दिए। डीईओ रहते हुए कमाल कर गए टीपी सिंह ने अतिशेष शिक्षकों के ट्रांसफर मामले में 5 दर्जन से भी अधिक न्यायालीन प्रकरण बनाए हैं। जिस पर वर्तमान डीईओ को खून-पसीना एक करना पड़ रहा है। नवागत डीईओ अभी भी इस पर कसरत कर रहे हैं।

होल्ड-अनहोल्ड का खेल

तब के डीईओ टीपी सिंह ने शिक्षकों के ट्रांसफर में होल्ड-अनहोल्ड का भी खेल खेला। डीईओ ने ट्रांसफर के लिए जो आवेदन मंगाए उस पर शिक्षकों ने पोर्टल में दिखाई गई रिक्तियों के आधार पर आवदेन कर दिया लेकिन जहां रिक्तियां दिख रहीं थी वह विद्यालय शून्य छात्र संख्या वाले थे। यही कारण था कि इनके ट्रांसफर नहीं हो सकते थे से इन मामलों के लिए पोर्टल होल्ड कर दिया गया। और जब इसे अनहोल्ड किया गया तो सारे के सारे पद भरे दिखने लगे। यहीं से मनमानी शुरू हुई और अपने खास लोगों को शून्य शिक्षकीय विद्यालयों में ट्रांसफर कर दिया गया लेकिन अंदरूनी आदेश दिए कि इनमें बच्चे दर्ज कराए जाएं। हालांकि कोरोना के कारण मामला दब गया लेकिन इसकी गंध अभी भी बाकी है। करीब 250 शिक्षकों को इसी तरह ट्रांसफर किया गया है। कुछ विद्यालय तो सतना शहर के अंदर के भी हैं।

अभी भी टीसी पर रोशन है डीईओ दफ्तर

जिले में कामचलाऊ डीईओ बैठाने की परंपरा पुरानी है। यहां बीते वर्ष में डीईओ रहे टीपी सिंह ने शिफ्टिंग के दौरान कई खेल किए। पहली कड़ी में अलमारियों को जिन वाहनों से ढोया उनके नंबर ज्यादातर स्कूटरों के थे। इसके बाद बिजली जलाने के नाम पर भी खेल कर दिया। पुराने पॉलीटेक्निक कॉलेज के डीईओ कार्यालय में काफी दिनों से परमानेंट बिजली कनेक्शन है लेकिन डीईओ रहे टीपी सिंह ने नए ऑफिस के लिए टीसी कनेक्शन ले लिया। इस कनेक्शन में भी क्रीड़ा मद से ही फीस भरी गई थी। मजेदार बात ये भी है कि अभी भी डीईओ का आलीशान ऑफिस टीसी कनेक्शन पर ही चल रहा है। सवाल ये है कि जो काम कम खर्चे में हो सकता था उस पर फिजूलखर्ची क्यों की गई? क्या जल्दबाजी में की व्यवस्था को सुधार नहीं जा सकता था? या फिर क्रीड़ा सेक्शन संभालने वाला बाबू की सिफारिश ज्यादा काम आई। बिजली कंपनी के नियमानुसार यहां नया कनेक्शन भी लिया जा सकता था।

दसवीं के विद्यार्थियों का स्कूलों से मांगा ब्योरा, भेजा गया फार्मेट

जबलपुर (नईदुनिया प्रतिनिधि)। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने 10वीं हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा को कोरोना संक्रमण के चलते निरस्त कर दिया था लेकिन अब बोर्ड परीक्षा परिणामों को लेकर तैयारी शुरू करने जा रहा है। इसके तहत सीबीएसई द्वारा सभी स्कूलों से विद्यार्थियों की जानकारी मांगी है। वहीं विद्यार्थियों की साल भर की गतिविधियों की जानकारियों की रिपोर्ट तैयार कर देने के लिए स्कूलों से कहा गया है जिसके आधार पर रिजल्ट तैयार किया जाएगा।

सभी स्कूलों को एक फार्मेट भेजा जा रहा है। इसमें सालभर हुए प्रोजेक्ट वर्क, असाइनमेंट आदि की जानकारी मांगी गयी है। इसके आधार पर रिजल्ट की तैयारी की जाएगी। सूत्रों के अनुसार स्कूलों को इसके लिए 15 बदुओं का फार्मेट भेजा गया है जिसके आधार पर जानकारी भरकर देने के लिए कहा गया है। इसमें छात्रों की पूरी जानकारी जिसमें सेक्शनवार छात्रों का नाम, उम्र, पिता का नाम, जाति,

परिणाम की तैयारी

- साल भर की गतिविधियों की मांगी गई रिपोर्ट
- सीबीएसई ने शुरू की रिजल्ट की तैयारी

पूर्व परीक्षा का परिणाम की डिटेल्स स्कूलों को भेजना है। स्कूल के टेस्ट में शामिल होने से लेकर टर्म परीक्षा में शामिल होने की जानकारी भी देनी होगी। गौरतलब है कि जिले में करीब 30 से अधिक सीबीएसई स्कूल हैं। दसवीं कक्षा की परीक्षाएं एक माह पूर्व होने वाली थी जिसे रदद किया जा चुका है। स्कूलों की समस्या है कि लॉकडाउन के चलते शिक्षण संस्थान बंद है ऐसे में कैसे जानकारी को जुटाया जाए। कई स्कूलों में स्टाफ खुद ही संक्रमित है तो वहीं स्कूल आने से डर रहे हैं।

कॉलेज मल्टीडिसिप्लिनरी स्ट्रीम में होंगे अपग्रेड, स्नातक स्तर पर नए शैक्षणिक सत्र से लागू होगा क्रेडिट सिस्टम

उच्च शिक्षा के क्षेत्र में मप्र में किया जा रहा बड़ा बदलाव, स्नातक पाठ्यक्रम में मनपंसद के विषय पढ़ सकेंगे छात्र

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

सतना. उच्च शिक्षा विभाग स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रम में बड़ा बदलाव करने जा रहा है। नए सत्र 2021-22 से क्रेडिट सिस्टम लागू होगा। विद्यार्थियों के सामने बीए, बीएससीए, बीकॉम जैसे पाठ्यक्रमों में विश्वविद्यालयों द्वारा विभिन्न संकाय के अंतर्गत तय विषयों के समूह को लेकर पढ़ाई करने की बाध्यता खत्म होगी। वे मूल विषयों के साथ मनपसंद विषय लेकर पढ़ाई कर सकेंगे। इसके लिए आगामी वर्षों में कॉलेजों को मल्टीडिसिप्लिनरी कॉलेज में अपग्रेड किया जाएगा, इसके लिए पूरा रोडमैप तैयार होगा। यह बदलाव नई शिक्षा नीति के अंतर्गत किए जा रहे हैं। ताकि विद्यार्थियों के ज्ञान में वृद्धि होने के साथ उनमें रोजगार परक कौशल विकसित हो सके।

अभी विद्यार्थी जिस कॉलेज में दाखिला लेगा उसमें पढ़ाए जाने वाले विषयों में से अपने पसंद के विषय का चयन कर पढ़ाई कर सकेगा। उदाहरण के तौर पर महाविद्यालय स्तर पर कला, वाणिज्य संकाय के अंतर्गत बीए,बीकॉम और बीसीए पाठ्यक्रम संचालित होते हैं। आगामी सत्र में जो छात्र किसी भी कोर्स में एडमिशन लेगा तो उसे तय कोर विषयों के अलावा उपलब्ध संकाय से जुड़े विषयों को इलेक्टिवि विषय के तौर पर पढ़ सकेगा। यानी वह वाणिज्य से जुड़े से विषयों के साथ इतिहास, राजनीतिशास्त्र जैसे भी विषय भी पढ़ सकेगा। इसके अलावा विद्यार्थियों को शिक्षा मंत्रालय व विभिन्न उच्च शैक्षणिक संस्थानों द्वारा कराए जाने वाले वोकेशनल कोर्स को करने की आजादी भी दी जाएगी।

बीच में पढ़ाई छूटी तो समय नहीं होगा बर्बाद : नई व्यवस्था के तहत विद्यार्थी किसी कारण से पढ़ाई छोड़ देता है तो उसने जितने समय पढ़ाई की है वह बर्बाद नहीं जाएगा। दरअसल, मल्टीपल एंट्री व एक्जिट नीति लागू की जाएगी। इसमें एक साल की पढ़ाई करने पर उसे सर्टीफिकेट,डिप्लोमा दिए जाएंगे। भविष्य में वह स्नातक की पढ़ाई पूरी करना चाहता है तो उसे वहीं से पढ़ाई करने का अवसर दिया जाएगा,जहां से उसने पढ़ाई छोड़ी थी।

फ्रेमवर्क तैयार करने हो चुकी 20 बैठक

इस मामले में उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव और मुख्यमंत्री की सहमति मिलने के बाद पूरा फ्रेमवर्क तैयार करने का कार्य तेजी से किया जा रहा है। अभी तक विश्वविद्यालयों, कॉलेजों के अधिकारियों व प्रोफेसर्स के साथ विभिन्न स्तरों पर 20 से अधिक बैठकें हो चुकी हैं। पूरे प्रदेश में नई व्यवस्था को लागू करने के लिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ स्टडीज की कमेटी गठित कर नए सिरे से पाठ्यक्रम तय कराया जा रहा है।

स्नातक में इस तरह होगी नई व्यवस्था

मूल विषय - पहले और दूसरे वर्ष में दो मूल विषय (कोर सब्जेक्ट) और अंतिम वर्ष में तीनों कोर विषय पढ़ने होंगे। अभी तक पाठ्यक्रम के लिए संबंधित संकाय से तीन कोर विषय लेना होता है। कोई छात्र बीएससी करता है तो उसे तीनो विषय विज्ञान संकाय के ही लेने होते हैं।

वैकल्पिक विषय - पहले और दूसरे वर्ष में दो मूल विषय के साथ तीसरा विषय कॉलेज में उपलब्ध मूल विषय से संबंधित संकाय या अन्य संकाय से जुड़ा एक विषय अपनी पसंद का पढ़ सकेगा। यानी अब कोई छात्र बीए करता है तो दो कोर विषय कला संकाय से और तीसरा विषय विज्ञान और वाणिज्य संकाय से जुड़ा ले सकेगा।

सह-पाठ्यक्रम गतिविधियां - अब आधार पाठ्यक्रम में पढ़ाए जाने वाले हिंदी, अंग्रेजी, पर्यावरण, उद्यमिता, कंप्यूटर विषय के साथ स्थान पर सह-पाठ्यक्रम गतिविधियों में विद्यार्थियों को हिस्सा लेना होगा। इसके तहत विभिन्न प्रोजेक्ट, ट्रेनिंग,ऑनलाइन कोर्स आदि करने की सुविधा मिल सकेगी।

नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने के लिए मुख्यमंत्री के निर्देश हैं। इसके तहत नई व्यवस्था लागू की जा रही है। इसके अंतर्गत विद्यार्थियों को मूल विषयों के साथ अपनी पसंद के विषय पढ़ने की आजादी मिल सकेगी। इससे ज्ञान में वृद्धि होने के साथ विद्यार्थी का कौशल विकसित हो सकेगा।

मोहन यादव, मंत्री, उच्च शिक्षा

एमपी बोर्ड की 10वीं-12वीं की परीक्षा को लेकर अभी भी असमंजस में विद्यार्थी

माशिमं की हेल्पलाइन पर 25 दिन में 25 हजार स्टूडेंट्स, पैरेंट्स ने किए काल, एक ही सवाल-जनरल प्रमोशन मिलेगा या परीक्षा होगी

पीपुल्स संवाददाता ● भोपाल
मो.नं. 9893231237

''मैम! कोरोना लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में 10-12वीं की परीक्षाएं होंगी या फिर जनरल प्रमोशन मिलेगा।... परीक्षाएं होंगी, तो किस पैटर्न पर होंगी।'' कुछ इस तरह के सवाल स्टूडेंट्स माध्यमिक शिक्षा मंडल (माशिमं) की हेल्पलाइन में कॉल करके पूछ रहे हैं।

ज्ञात हो कि कोरोना संक्रमण फैलने के कारण बोर्ड परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है, लेकिन अभी तक नया शेड्यूल नहीं बताया गया है। ऐसे में मंडल की हेल्पलाइन नंबर 18002330175 पर कॉल्स की संख्या बढ़ गई है। अभी हेल्पलाइन शुरू हुए 25 दिन ही हुए हैं, लेकिन कॉल की संख्या 25 हजार से ऊपर पहुंच गई है। आलम यह है कि प्रत्येक दिन एक हजार से अधिक स्टूडेंट्स और उनके पैरेंट्स यहां काल कर जानकारी ले रहे हैं। सामान्य दिनों में 300 से 500 कॉल रोजाना आते थे।

तीन शिफ्टों में चार-चार काउंसलर कर रहे समाधान: माध्यमिक शिक्षा मंडल की हेल्पलाइन तीन शिफ्टों में संचालित की जा रही है। पहली शिफ्ट में सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक चार लोग और दूसरी शिफ्ट में दोपहर 2 से शाम 6 बजे तक चार लोग काउंसलिंग कर रहे थे। सुबह 8 से रात 8 बजे तक तीन शिफ्टों में 12 काउंसलर सवालों का जवाब दे रहे हैं।

बीते सालों में कॉल की स्थिति

2018 में 1 लाख 6 हजार कॉल आए।
2019 में 1 लाख 23 हजार कॉल आए।
2020 में 2 लाख 35 हजार काल आए।
1 अप्रैल 2021 से 25 दिन में : 25 हजार कॉल आए।

80% विद्यार्थी और 20 फीसदी पैरेंट्स व टीचर पूछते हैं सवाल

हेल्पलाइन पर आने वाले कॉल्स में 80 फीसदी कॉल विद्यार्थियों के होते हैं। 10 फीसदी शिक्षक और 10 फीसदी अभिभावक कॉल कर रहे हैं। वहीं हेल्पलाइन पर आने वाले कॉल्स में 70 फीसदी कॉल एकेडमिक व कॅरियर से संबंधित होते हैं।

पैरेंट्स को बच्चों की चिंता

कोरोना काल में 10वीं एवं 12वीं की परीक्षाएं स्थगित किए जाने से स्टूडेंट परेशान हैं। वह पूछ रहे हैं कि बोर्ड परीक्षाएं होंगी या नहीं, यदि होंगी तो किस पैटर्न पर होंगी। पैरेंट्स को इस कोरोना की भयावहता को देखते हुए बच्चों की चिंता सता रही है।
डॉ. हेमंत शर्मा, प्रभारी, एमपी बोर्ड हेल्पलाइन

स्थापना के आठ साल बाद विवि में शिक्षा व्यवस्था को पटरी पर लाने की कवायद

हिंदी विश्वविद्यालय में डेढ़ दर्जन असिस्टेंट प्रोफेसरों की होगी भर्ती, रोस्टर जारी कर 21 दिन में मंगाईं आपत्तियां

पीपुल्स संवाददाता ● भोपाल
मो.नं. 9893231237

अटल विहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय, डेढ़ दर्जन असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती की तैयारी में हैं। इसके लिए रोस्टर जारी कर दिया गया है। रोस्टर में विवि ने आपत्तियां मंगाई हैं। आपत्तियों के निराकरण के बाद भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाएगा। इसके बाद योग्य उम्मीदवार आवेदन कर पाएंगे।

हिंदी विश्वविद्यालय में आठ साल बाद असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। हालांकि इन आठ सालों में विश्वविद्यालय में 9 असिस्टेंट प्रोफेसरों के पद बढ़ गए हैं। बताया

जाता है कि हिंदी विश्वविद्यालय ने छह प्रोफेसर और तीन एसोसिएट प्रोफेसर के पदों को असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों में परिवर्तित करा लिया है, क्योंकि वर्ष 2013 में जारी विज्ञापन में 9 ही असिस्टेंट प्रोफेसर के पद थे, जो अब 18 हो गए हैं। रजिस्ट्रार यशवंत पटेल ने आदेश जारी कर आपत्ति दर्ज कराने के लिए 21 दिनों का समय दिया है। उम्मीदवार रजिस्ट्रार के नाम से डाक से आपत्तियां भेज सकते हैं।

इन विषयों के लिए असिस्टेंट प्रोफेसरों की होनी है भर्ती

अर्थशास्त्र, इंजीनियरिंग, इतिहास एवं प्राचीन भारतीय इतिहास, कृषि विज्ञान, पत्रकारिता एवं संचार, प्रबंधन एवं वाणिज्य, भारतीय दर्शन एवं ज्ञान परंपरा, भौतिक शास्त्र, योग एवं मानव चेतना, रसायन, वनस्पति, विधि, समाजशास्त्र एवं समाजकार्य, संगणक, हिंदी भाषा एवं अनुवाद, राजनीति विज्ञान एवं लोक प्रशासन तथा प्राणि शास्त्र के एक-एक पद पर असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती होनी है।

नए सत्र तक नियमित टीचर्स की भर्ती की तैयारी

अभी तक हिंदी विश्वविद्यालय किराए के भवन में चल रहा था। इसकी वजह से

बहुत सारी व्यवस्थाएं ठीक नहीं हो पाई थीं। अब विश्वविद्यालय खुद के भवन में पहुंच गया है। कवर्ड हॉस्टल के साथ यहां पर कम फीस में अच्छी शिक्षा मिलेगी तो अवश्य ही स्टूडेंट्स की संख्या बढ़ेगी। रोस्टर जारी कर दिया गया है, ताकि नए सत्र तक नियमित टीचर्स की भर्ती की जा सके।

यशवंत पटेल, रजिस्ट्रार, अटल बिहारी हिंदी विवि, भोपाल

4 साल में सरकार ने 347 छात्रों को दिल्ली में कराई UPSC की कोचिंग

8.54 करोड़ खर्च करने के बावजूद एससी वर्ग का एक भी छात्र नहीं बन सका IAS

सीताराम ठाकुर ● भोपाल
मो.नं. 9425078939

मप्र सरकार हर साल अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के प्रतिभावान छात्रों को सिविल सेवा परीक्षा (यूपीएससी) में पास कराने के लिए उनकी कोचिंग पर करोड़ों रुपए खर्च करती है, लेकिन बीते चार साल में इस वर्ग के एक भी छात्र का यूपीएससी में चयन नहीं हुआ। सरकार ने इस दौरान 347 छात्रों की कोचिंग पर 8.54 करोड़ रुपए विभिन्न कोचिंग संस्थाओं पर खर्च भी कर दिए, जबकि इन कोचिंग से अन्य वर्ग के छात्र हर साल आईएएस बन रहे हैं। प्रदेश के अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के प्रतिभावान छात्रों को विदेश की पढ़ाई ही नहीं, बल्कि देश में होने वाली सिविल सेवा परीक्षा (यूपीएससी) के लिए भी हर साल मप्र सरकार छात्रों का चयन कर उन्हें कोचिंग के लिए दिल्ली भेजती है। जिन उच्च स्तर की कोचिंग संस्थाओं में इन छात्रों को परीक्षा पूर्व तैयारी की कोचिंग कराई जाती है, उनमें से हर साल अन्य वर्ग ओबीसी, जनरल के छात्र आईएएस तो बन रहे हैं, लेकिन अनुसूचित जाति वर्ग के नहीं। खासकर इस वर्ग के छात्र प्री परीक्षा क्वालिफाई और मेन परीक्षा क्वालिफाई नहीं कर पाते, जिससे वे इंटरव्यू तक पहुंचते ही नहीं है, जिसके कारण सरकार का करोड़ों रुपए हर साल बेकार जा रहा है।

पीपुल्स समाचार
पड़ताल

फाइल फोटो

कोचिंग पर किस साल कितनी राशि खर्च

वर्ष	छात्रों का चयन	खर्च राशि
2016-17	93	264.12
2017-18	81	226.35
2018-19	89	282.97
2019-20	84	80.78
राशि		854.23
कुल छात्र		347

स्त्रोतः आदिम जाति विभाग -राशि लाख में

दिल्ली की इन संस्थाओं में कराई गई कोचिंग

दिल्ली की जिन संस्थाओं में इन छात्रों की कोचिंग कराई जाती है, उनमें बाजीराम एंड रवि इंस्टिट्यूट फॉर आईएएस, अल्टरनेटिव लर्निंग सिस्टम प्रायवेट लिमिटेड, दृष्टि द विजन, कैरियर प्लस एजुकेशन संस्थान तथा श्रीराम आईएएस नई दिल्ली शामिल हैं।

इस साल भी कोचिंग से वंचित रहेंगे छात्र

कोरोना संक्रमण की वजह से राज्य सरकार ने वर्ष 2020-21 में एक भी छात्र का चयन यूपीएससी की कोचिंग के लिए किसी भी छात्र का नहीं किया था और इस साल भी कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है, जिसके कारण किसी भी छात्र का चयन होने की संभावना नहीं है।

सरकार के प्रयास सफल नहीं हुए, आगे होंगे

अनुसूचित जाति वर्ग के छात्रों को यूपीएससी की कोचिंग कराने और उनके सफल होने के लिए सरकार ने एक-एक छात्र पर लाखों रुपए खर्च किए है, लेकिन सरकार के प्रयास सफल नहीं हुए। हमारी सरकार अब इस मामले में प्रयास तेज करेगी और अगले सालों में छात्र सफल होंगे।

कृष्णा गौर, विधायक, गोविंदपुरा

प्री और मेन परीक्षा क्वालिफाई नहीं कर पाते

जिन छात्रों का चयन यूपीएससी के लिए कर हम उन्हें दिल्ली भेजते हैं, उनमें से अधिकांश छात्र प्री परीक्षा और मेन परीक्षा क्वालिफाई ही नहीं कर पाते, जिसके कारण वे इंटरव्यू तक नहीं पहुंचते हैं। वर्ष 2018-19 के छात्रों की कोचिंग के लिए 6 माह का अतिरिक्त समय दिया गया है, संभावना है कि एक-दो छात्र इस बार इंटरव्यू तक पहुंच सकें।

सुधीर कुमार जैन, अपर संचालक, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग

मरीजों को लगने वाले बाजार में ब्लैक में बेच दिए रेमडेसिविर, दो अस्पतालों के पांच कर्मचारी बंदी

उज्जैन। इंदौर के बाद उज्जैन में भी मरीज को लगाने की बजाय रेमडेसिविर इंजेक्शन बाजार में बेचे जा रहे थे। पुलिस ने जाल बिछाकर देशमुख अस्पताल के तीन और आरडी गार्डी मेडिकल कॉलेज से जुड़े पांच कर्मचारियों को गिरफ्तार कर लिया। इनमें तीन लोग फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं। रविवार को थाना चिमनगंज व साइबर टीम को रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी की सूचना मिली। पुलिस को बताया गया कि अलाउंस सिटी के सामने आगर रोड उज्जैन पर तीन लोग रेमडेसिविर ऊंचे दामों पर बेचने के लिए ग्राहक तलाश रहे हैं। पुलिस ने तीन आरोपियों से दो इंजेक्शन अवैध रूप से ऊंचे दामों में कालाबाजारी करते हुए पाए जाने पर गिरफ्तार कर लिया। इनसे एक इंजेक्शन, एक्टिवा जब्त कर गिरफ्तार किया गया। उक्त तीनों आरोपियों द्वारा रेमडेसिविर किसी अन्य दो व्यक्तियों से खरीदना बताया गया। दोनों की तलाशी पर एक रेमडेसिविर व एंटी बायोटिक इंजेक्शन मिले। पूछताछ में आइसोलेशन वार्ड में काम करने वाले तीन साथियों से इंजेक्शन खरीदना बताया है। तीनों से एक रेमडेसिविर व एक एंटी बायोटिक इंजेक्शन जब्त किया गया। आरोपियों ने गुनाह कबूल कर लिया है। गिरोह के मास्टर माइंड कुलदीप, राजेश और सरफराज हैं। तीनों देशमुख अस्पताल के आईसोलेशन वार्ड में काम करते हैं।

नर्सिंग कॉलेज ने निकाली फर्जी भर्ती जनसंपर्क को करना पड़ा खंडन

आवेदन लेकर पहुंचने लगे कई अभ्यर्थी

मंदसौर,(आरएनएन)। श्रीजी नर्सिंग कॉलेज मंदसौर द्वारा फर्जी अस्थाई नर्सिंग स्टाफ की भर्ती निकली गई है। जिसको लेकर कई अभ्यर्थी जिला चिकित्सालय में आवेदन लेकर पहुंचने लगे। जिला अस्पताल द्वारा तो कई भर्ती नहीं निकाली गई जिसके बाद स्थिति को स्पष्ट करने के लिए जनसंपर्क विभाग ने प्रेस नोट जारी कर बताया कि जिला अस्पताल द्वारा कोविड सेंटर पर अस्थाई नर्सिंग स्टॉफ की कोई भर्ती नहीं निकली गई है। श्रीजी नर्सिंग कॉलेज द्वारा जो भर्ती निकाली गई है वो फ्जी भर्ती है।

इसके संचालक मंदसौर निवासी दीपक सैनी पर भी कई बार कई आरोप लग चुके है। थाने में भी उनके विरुद्ध प्रकरण दर्ज हो चुके है। लेकिन इस बार तो नर्सिंग कॉलेज संचालक ने अति ही कर दी और नौबत यहां तक आ गई कि जिला चिकित्सालय की ओर से जनसम्पर्क विभाग को खंडन जारी करना पड़ गया।

वहीं श्रीजी नर्सिंग कॉलेज के संचालक दीपक सैनी से इस बारे में चर्चा कि गई तो उन्होने बताया कि भर्ती हमारे द्वारा नहीं निकाली गई है भर्ती एनएचएम (नेशनल हेल्थ मिशन) की ओर से निकाली गई है जिसका लेटर नीमच तो पहुंच गया है लेकिन मंदसौर सीएमएचओ के पास नहीं पहुंचा है जिसके कारण यह असमंजस की स्थिति बनी है। हमारे द्वारा कोई फर्जी भर्ती नहीं निकाली गई है आप खुद देखना दो से तीन दिनों में भर्ती का लेटर मंदसौर सीएमएचओ के पास भी पहुंच जाएगा।

शिक्षक अध्यापक संवर्ग को पड़ रहे वेतन के लाले

स्टार समाचार | अतरैला

जिले के जवा सहित अन्य ब्लॉकों के अध्यापक शिक्षक संवर्ग का माह- मार्च 2021 से वेतन डीडीओ पावर्स समाप्त हो जाने के कारण लंबित पड़ा है। जिले के तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी आरएन पटेल के स्थानांतरण उपरांत नवीन जिला शिक्षा अधिकारी के प्रभार का दायित्व केपी तिवारी को सौंपा गया है। जिन्हें डीडीओ पावर्स सम्बन्धी कार्यवाही के उपरांत आज तक नहीं दिया गया है। इसी परिपेक्ष्य में रीवा जिले के कई विकास खंडों में आहरण संवितरण अधिकारी विकास खंड शिक्षा अधिकारी के डीडीओ पावर्स की भी समय सीमा समाप्त हो गई हैं। नवीन डीईओ को भी अभी तक डीडीओ पावर प्रदान नहीं किए गए हैं। जिसके चलते जिला अंतर्गत कई विकास खंडों के विकास खंड शिक्षा अधिकारी के डीडीओ पावर्स रिन्यूवल नहीं हो पा रहे हैं। जिसके कारण मिली जानकारी के अनुसार हजारों अध्यापक शिक्षक सम्वर्ग का वेतन माह मार्च से भुगतान होना लंबित हैं। जिससे कर्मचारियों को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है, सभी शिक्षक संवर्ग के कर्मचारियों में निराशा व्याप्त है और उनकी आर्थिक स्थिति चरमरा गई है। आजाद अध्यापक शिक्षक संघ के प्रान्तीय उपाध्यक्ष राजेश सिंह, प्रमोद चतुर्वेदी, संजय सिंह, पुष्पेंद्र द्विवेदी, बालेंदुशेखर द्विवेदी, इंद्रलाल वर्मा आदि ने कलेक्टर से नवपदस्थ जिला शिक्षा अधिकारी को डीडीओ पावर जारी कराए जाने की मांग की गई है।

जंगली सुअर कर रहे फसलों को चौपट

गुढ़। गुढ़। गुढ़ क्षेत्र के किसान एक बार फिर जंगली जानवरों से परेशान है। क्षेत्र के उमरी, धांधी, हर्दी, करौंदी, महडाड़ी, बेला, खामडीह, चौड़ियार, हरदुआ, अतरारी, गांव के किसानों ने बताया कि पहले जंगली जानवर नील गाय के आतंक से किसानों की फसले पूरी तरह से चट कर ली गई। अब वर्तमान समय मे इन गांव के लोग जंगली सुअर के आतंक से भारी परेशान है। उमरी निवासी बृजेन्द मिश्रा, रामनिवास मिश्रा, हर्दी निवासी बृजेश शुक्ला, पप्पू शुक्ला सहित गांव के किसानों ने बताया कि इस समय किसानों द्वारा खेतो मे बोई गई सांग सब्जी को वन सुअर भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं।

दो हजार प्रोफसरों को दिया गया प्रशिक्षण

मप्र के 516 कॉलेजों में से 473 में प्रभारी प्राचार्य किया पदस्थ

स्टार समाचार | भोपाल

उच्च शिक्षा विभाग प्रोफेसरों की अंतिम वरिष्ठता सूची को जारी नहीं कर सकता है। इसमें जहां सीधी भर्ती और पदोन्नति ने मामला उलझा रखा है। वहीं आरक्षण का प्रतिशत फाइनल नहीं होने के कारण विभाग को प्रोफेसरों को प्राचार्य बनाने में काफी परेशानी आ रही है। इस कारण विभाग ने आरक्षण और वरिष्ठता को नजरअंदाज कर प्रशिक्षण प्राप्त प्रोफेसरों को प्राचार्य बनाएगा। इसके लिए करीब दो हजार प्रोफेसरों को प्रशिक्षण दिया गया है। विभाग प्रोफेसरों की अंतिम सूची करता है, तो प्रोफेसर हाईकोर्ट में सूची के खिलाफ याचिका दायर कर देते हैं। वहीं आरक्षण लागू करने का मामला सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों पर छोड़ रखा है।

इसके बाद भी शासन प्रोफेसरों को पदोन्नति देकर प्राचार्य बनाने की गुत्थी को नहीं सुलझा पा रहा है, इसलिए चयनित दो हजार प्रोफेसरों को प्रशासन अकादमी से ट्रेनिंग दी जा चुकी है। अब उन्हें प्राचार्य बनाया जाएगा। वर्तमान में प्रदेश के 516 यूजी-पीजी कालेज में से सिर्फ 43 प्राचार्य नियमित हैं। इसमें से तीन भोपाल में पदस्थ हैं, जिसमें स्टेट लॉ कालेज में सुधा बैसा और भेल कालेज में मथुरा प्रसाद पदस्थ हैं।

प्रभारी में हो रहे आए दिन विवाद

478 कालेजों में विभाग ने वरिष्ठ प्रोफेसर के अलावा जूनियर प्रोफेसर को प्रभारी प्रावार्य नियुक्त किया है। इससे कालेजों में आए दिन विवाद होते हैं। वही कई कालेजों में वरिष्ठ प्रोफेसर प्रभारी प्राचार्य रहना नहीं चाहते हैं, इसलिए विभाग को कई वरिष्ठ प्रोफेसरों ने प्रभारी प्राचार्य का पद छोड़ने के लिए आवेदन किए हैं।

विभाग ने 46 असिस्टेंट प्रोफेसर को दो शर्तें लगाकर दी मंजूरी

सख्ती : PHD और कोर्सवर्क करने प्रोफेसर्स को नहीं मिलेगी स्टडी लीव

प्रदेश के प्रोफेसर स्टडी लीव के नाम पर फॉरेन ट्रिप कर आते हैं। यहां तक अध्ययन अवकाश के बहाने वे अपनी फैमिली के साथ हिल स्टेशन का लुत्फ लेते हैं। इसलिए उच्च शिक्षा विभाग ने स्टडी लीव की व्यवस्था को खत्म कर दिया है। अब प्रोफेसरों को पीएचडी और कोर्स वर्क करने के लिए स्वयं के संचित अवकाश लेने होंगे।

M.P. Higher Edu. Department

प्रदेश टुडे संवाददाता, भोपाल

उच्च शिक्षा विभाग अपने प्रोफेसरों को पीएचडी करने करीब तीन साल की स्टडी लीव देता है। प्रोफेसरों ने स्टडी लीव का फायदा काफी गलत तरीके से उठाया है। वे पीएचडी से ली गई लीव में विदेश यात्रा, फैमिली टूर के अलावा हिल स्टेशन का सैर सपाटा करते रहे हैं। लीव पर लौटने के बाद प्रोफेसरों की पीएचडी तक पूरी नहीं होती थी, इससे विभाग को काफी नुकसान होता है। लीव पर गए प्रोफेसर की कक्षाओं को पढ़ाने के लिए विभाग को दूसरे प्रोफेसर की व्यवस्था एडोक या स्थानांतरण से करना होती थी। इससे विभाग को काफी आर्थिक नुकसान होता है। इसलिए विभाग ने 46 असिस्टेंड प्रोफेसरों की सूची जारी कर उन्हें पीएचडी और कोर्सवर्क करने की स्वीकृति दे दी है। उन्हें दो शर्तों में बांध दिया है कि वे स्टडी लीव नहीं मांगेंगे और उनके पीएचडी और कोर्सवर्क करने पर अध्ययन व्यवस्था प्रभावित नहीं होगी।

प्रदेश टुडे एजुकेशन

शासन का तर्क: कोई फायदा नहीं बल्कि होता है नुकसान

पीएचडी करने पहले साल की स्टडी लीव, इसके बाद एक माह का एक्सटेंशन और थीसिस जमा नहीं होने की दशा में अवकाश में छह माह का बढ़ोतरी कर हो जाती है। सरकार का ऐसा तर्क है कि पीएचडी करने से शासन को कोई फायदा नहीं होता है। क्योंकि पीएचडी से प्रोफेसर को व्यक्तिगत लाभ होता है। यहां तक उन्हें तीन से पांच वेतनवृद्धि मिल जाती है। इसलिए शासन उन्हें स्टडी लीव देकर स्वयं का नुकसान क्यों करे। इसलिए प्रोफेसरों को पीएचडी और कोर्सवर्क स्वयं के अवकाश पर करना होंगे।

कोरोना ने दिया ऑनलाइन का सहारा: वर्तमान में कोरोना संक्रमण पूरे देश में छाया हुआ है। इससे प्रोफेसर जहां कोर्सवर्क की कक्षाएं ऑनलाइन ले सकते हैं। वहीं वे अपने स्टूडेंट की कक्षाएं ऑनलाइन लगा सकते हैं। यहां तक पीएचडी कराने वे अपने सुपरवाईजर से ऑनलाइन मार्गदर्शन हासिल कर सकते हैं।

शोध उपाधि प्राप्त करने पर वेतनमान में तीन अग्रिम वेतनवृद्धि की पात्रता बनती है। साथ ही वरिष्ठ और प्रवर वेतनमान में समय सीमा कम होती है। इसके अलावा शोधकार्य से शिक्षक को व्यक्तिगत लाभ होता है, लेकिन सरकार को हानि जरुर होता है। इसलिए स्टडी लीव पर शायद प्रतिबंध लगाया गया है।
- डॉ. राधा वल्लभ शर्मा
पूर्व प्राचार्य, स्टेट लॉ कालेज

कोरोना से जंग • हाथोहाथ जारी हुईं सभी जरूरी मंजूरियां, मंगलवार से मिलेगी रोज 40 टन ऑक्सीजन

इंदौर में 3 साल से बंद 40 टन का ऑक्सीजन प्लांट 90 के बजाय 11 दिन में तैयार किया

अच्छी खबर : प्लांट में ट्रायल उत्पादन भी शुरू

भास्कर न्यूज | इंदौर

सौ लोगों की टीम ने 11 दिन की कड़ी मेहनत से 90 दिन में तैयार होने वाला ऑक्सीजन प्लांट 11 दिन में तैयार कर दिया। पीथमपुर के इस प्लांट में रविवार रात से ट्रायल उत्पादन शुरू हो गया है। 24 घंटे शुद्धता जांच के बाद मंगलवार से 40 टन ऑक्सीजन रोज मिलने लगेगी। एकेवीएन एमडी रोहन सक्सेना ने बताया कि करण मित्तल का प्लांट तीन साल से बंद पड़ा था। उनसे बात की तो बोले चालू करने में 3 महीने लगेंगे। सभी विभागों ने जरूरी मंजूरियां हाथोंहाथ जारी की। प्लांट तक सड़क बनाई। नतीजा प्लांट शुरू हो गया। इसके लिए मित्तल ने 40 लाख खर्च किए। मुंबई से ऑक्सीजन मीटर व अहमदाबाद से अन्य मशीनें मंगवाई गई। प्लांट इंचार्ज मदन अग्रवाल की मदद के लिए अहमदाबाद से तीन इंजीनियर आए। 14 अप्रैल से प्लांट पर काम शुरू हुआ। एक भी दिन काम नहीं रोका गया। मोयरा सरिया ने मैकेनिकल हैंड व लेबर उपलब्ध कराए तो अन्य कंपनियों ने दूसरी सामग्री दी। इधर, प्रदेश के थर्मल पॉवर स्टेशंस के माध्यम से भी ऑक्सीजन का उत्पादन होगा।

▪ इंदौर में रविवार को 1841 नए मरीज मिले जबकि 7 लोगों की कोरोना से मौत हो गई।

ग्लोब मास्टर ने 3 फेरे में इंदौर से 4 टैंकर जामनगर पहुंचाए

इंदौर | ऑक्सीजन के लिए मदद का कारवां बढ़ता जा रहा है। शनिवार को रिलायंस इंडस्ट्रीज से सरकार को सूचना दी गई कि आप जरूरत के मुताबिक कितनी भी ऑक्सीजन जामनगर से ले सकते हैं। इस पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पीएम नरेंद्र मोदी से बात की। नतीजा यह हुआ कि रविवार को विमान सीए-17 ग्लोब मास्टर ने तीन फेरे में इंदौर से 4 टैंकर जामनगर पहुंचा दिए। सोमवार को वहां से 92 टन ऑक्सीजन मिल सकेगी। सोमवार को भी दो बार विमान के इंदौर आने का शेड्यूल आ चुका है।

परिजन को बिना सूचना दिए बुजुर्ग को डिस्चार्ज किया, 20 घंटे बाद क्यारी में पड़े मिले, मौत

इंदौर | सुपर स्पेशिएलिटी अस्पताल में परिवार को सूचना दिए बिना 65 वर्षीय कोरोना मरीज को शनिवार शाम डिस्चार्ज कर दिया गया। रविवार को कुशल जानने पहुंचे उनके बेटे शिव कॉलोनी निवासी हेमंत धानु को हकीकत पता चली तो उनके होश उड़ गए। आपत्ति के बाद प्रबंधन ने कर्मचारियों को ढूंढने भेजा। दोपहर में बुजुर्ग अस्पताल परिसर में ही एक क्यारी में पड़े मिले। रात में उनकी मौत हो गई। हेमंत धानु का आरोप है कि शनिवार को मैं आया, लेकिन स्टाफ ने उनके बारे में कुछ नहीं बताया। रिसेप्शन पर डिस्चार्ज करने की एंट्री तक नहीं थी। घर ले जाने के बाद उनकी तबीयत बिगड़ी तो एक निजी अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। वहीं अस्पताल के सहायक अधीक्षक डॉ. डीके शर्मा का कहना है कि डिस्चार्ज करने की सूचना पहले ही दे दी गई थी। वे नहीं पहुंचे।

बिल पर विवाद... डॉक्टर व परिजन के बीच मारपीट

इंदौर | चंदननगर के चिरायु अस्पताल में बिल की राशि को लेकर विवाद के चलते डॉक्टर व परिजन में जमकर मारपीट हुई। पुलिस ने दोनों पक्षों की तरफ से मारपीट का केस दर्ज किया है। राजमोहल्ला निवासी कृतिका वर्मा का आरोप है कि पिता रवि को एक दिन पहले वहां भर्ती किया था। जनरल वार्ड में पलंग का किराया 3 हजार बताया था। 20 हजार एडवांस जमा किए थे। रविवार को डिस्चार्ज कराना चाहा तो डीलक्स वार्ड का चार्ज लगाकर 19 हजार का बिल दे दिया। बिल कम करने को कहा तो डॉक्टर ने मारपीट शुरू कर दी। डॉ. जाट ने भी मारपीट का केस दर्ज कराया है।

कटनी कलेक्टर ने कहा- मरीजों को डिस्चार्ज करें

कटनी | ऑक्सीजन संकट की आशंका के चलते रविवार को कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने अनुबंधित निजी अस्पतालों को मोबाइल पर संदेश भेजकर ऑक्सीजन बेड नहीं बढ़ाने के निर्देश दिए। कहा गया कि कम गंभीर मरीजों को तत्काल डिस्चार्ज किया जाए। ऑक्सीजन की खपत न्यूनतम रखी जाए। दो दिन इसी तरह निकालने पड़ेंगे। मैसेज वायरल होते ही मरीजों के परिजन ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर अस्पताल पहुंचने लगे। शाम को तीन मीट्रिक टन ऑक्सीजन पहुंचने पर प्रशासन ने राहत की सांस ली।

ग्वालियर में ऑक्सीजन पर दरोगा और डॉक्टर भिड़े

ग्वालियर | पिंटो पार्क स्थित ऑक्सीजन प्लांट पर रविवार शाम डॉक्टर और सब इंस्पेक्टर के बीच जमकर मारपीट हुई। रुद्राक्ष हॉस्पिटल के डॉ. अभिषेक राजपूत सिलेंडर लेने वहां पहुंचे थे। पहले सरकारी अस्पतालों को ऑक्सीजन देने की बात पर बहस शुरू हो गई। महाराजपुरा थाने के दरोगा रामकिशोर जोशी ने डॉक्टर को थप्पड़ मार दिया। डॉक्टर ने मारपीट शुरू कर दी। बाद में राजीनामा हो गया। रविवार को ग्वालियर में 1208 नए मरीज मिले। जबकि कोविड वार्ड में भर्ती 44 लोगों ने दम तोड़ दिया।

जब 10 फीसदी उपस्थिति के निर्देश तो कैसे बुला सकते हैं सभी कर्मचारियों को

भोपाल (आरएनएन)। महामारी संक्रमण से बचाव को लेकर एक ओर राज्य सरकार ने समस्त सरकारी कार्यालयों में मात्र 10 प्रतिशत उपस्थिति निर्धारित की है। वहीं भोपाल संभाग आयुक्त कार्यालय में प्रतिदिन शत प्रतिशत कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जा रही है। कमिश्नर कार्यालय की इस व्यवस्था के विरोध में सरकारी कर्मचारी खड़े हो गए है। मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष जितेन्द्र सिंह ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा है कि राज्य मंत्रालय और सतपुड़ा से लेकर विंध्यांचल सहित संभाग जिला एवं ब्लॉक कार्यालय तक 10 फीसदी उपस्थिति राज्य सरकार द्वारा अनिवार्य की गई है। उसके बाद भी संभागीय कार्यालय में प्रतिदिन कर्मचारियों की शत प्रतिशत मौजूदगी दर्ज करवाई जा रही है। कर्मचारी संघ अध्यक्ष का आरोप है कि जो सेवक ड्यूटी करने नहीं पहुंच रहा है उसको कार्यवाही का भय दिखाया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि कार्यालय के कई कर्मचारी संक्रमित हो चुके है। फिर भीआदेश के अनुसार वहां ड्यूटी नहीं लगाई जा रही है।

निलंबित मेडिकल स्टाफ होगा बहाल, 186 डॉक्टरों पर होगी कार्रवाई

प्रशासनिक संवाददाता ■ भोपाल

मध्य प्रदेश सरकार ने मेडिकल इमरजेंसी के मद्देनजर अस्पतालों में स्टाफ की कमी को देखते हुए सस्पेंडेट नर्सिंग और पेरामेडिकल स्टाफ को बहाल करने का फैसला लिया है। इसके साथ ही ड्यूटी ज्वाइन नहीं करने वाले 186 डाक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए आने वाले दिनों स्टाफ की आपूर्ति बड़ी चुनौती है। इसको देखते हुए स्वास्थ्य आयुक्त ने नर्सिंग स्टाफ और पेरामेडिकल के निलंबित कर्मचारियों को बहाल कर कोरोना में ड्यूटी लगाने के आदेश दिए हैं।

तत्काल प्रभाव से सेवा वापसी के आदेश

स्वास्थ्य आयुक्त आकाश त्रिपाठी ने सभी क्षेत्रीय संचालकों को भेजे आदेश में निलंबित तृतीय श्रेणी नर्सिंग और पेरामेडिकल स्टाफ, लैब टेक्नीशियन, कम्पाउंडर, फार्मासिस्ट, रेडियोग्राफर को तत्काल प्रभाव से सेवा में वापसी करने को कहा है। मैदानी कर्मचारियों एएनएम, एमपीडब्लू पर्यवेक्षक, बीईई को बहाल कर कोरोना मरीजों के इलाज संबंधी सेवाओं में ड्यूटी लगाने के आदेश भी दिए हैं।

डाक्टर्स के खिलाफ एक्शन की तैयारी

पिछले दिनों भोपाल, इंदौर के सरकारी कालेजों में इंटर्नशिप पूरी करने वाले 235 डाक्टर्स को नौकरी ज्वाइन करने के आदेश जारी हुए थे, लेकिन इसमें से 186 डाक्टर कोरोना के बढ़ते मामलों में ड्यूटी करने से बच रहे हैं। इसको देखते हुए अब स्वास्थ्य आयुक्त ने चिकित्सा शिक्षा आयुक्त को पत्र लिखकर इनके खिलाफ कार्रवाई करने को कहा है। गौरतलब है कि इंदौर के एमवाय मेडिकल कॉलेज से पास हुए और भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज से इंटर्नशिप करने वाले डाक्टर्स को बॉन्ड भराकर ग्रामीण सेवा के तहत पोस्टिंग दी गई है। इन डाक्टर्स को 15 दिनों में ज्वाइन करना था। इसके साथ ही इनको एक साल तक ग्रामीण क्षेत्रों में सेवाएं देने के लिए कहा गया था।

इन जिलों में हुई थी डॉक्टरों की पोस्टिंग

स्वास्थ्य विभाग के आंकडों के अनुसार भोपाल में 48, इंदौर में 32, सीहोर में 14, उज्जैन में 13, रतलाम में 9, बड़वानी में 8, बुरहानपुर में 7, खंडवा और देवास में 6-6, राजगढ़ और बैतूल में 5-5, होशंगाबाद, खरगोन, शाजापुर, विदिशा और नीमच में 4-4, धार और रायसेन में 3-3, हरदा और मंदसौर में 2-2, झाबुआ और अलीराजपुर में 1-1 डॉक्टर ने अब तक ज्वानिंग नहीं दी है।

नई खोज डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी ने कहा- कोरोना अब अंतिम महामारी

वैज्ञानिकों ने बनाई ऐसी माइक्रोचिप, जो वायरस को खून से फिल्टर कर शरीर से निकाल देगी

वॉशिंगटन, एजेंसी। अमेरिकी रक्षा विभाग के मुख्यालय पेंटागन के वैज्ञानिकों ने एक ऐसी माइक्रोचिप और तकनीक विकसित की है, जो आपके शरीर में कोरोना वायरस के लक्षण को बेहद आसानी से पहचान लेगी और बाद में वायरस को फिल्टर के जरिए खून से निकाल लिया जाएगा। इस नई तकनीक को डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी (डीएआरपीए) ने विकसित किया है। इसे बनाने वाली टीम के प्रमुख महामारी विशेषज्ञ रिटायर्ड कर्नल डॉ. मैट हेपबर्न ने यह दावा भी किया कि कोविड-19 अंतिम महामारी होगी। अब हम भविष्य में किसी भी प्रकार के जैविक और रासायनिक हमले से बचाव के लिए पूरी तरह तैयार हैं। डॉ. हेपबर्न ने कहा कि माइक्रोचिप को शरीर के किसी भी हिस्से में त्वचा के नीचे लगाया जा

सकता है। यह शरीर में होने वाली हर तरह की रासायनिक प्रतिक्रिया बताएगी और उसके द्वारा भेजे जाने वाले संकेत बताएंगे कि आप कितनी देर में ■ शेष पृष्ठ 9 पर

3 से 5 मिनट में मिलेगा रिजल्ट

डॉ. हेपबर्न ने टिश्यू जैसे जेल को दिखाते हुए बताया कि यह माइक्रोचिप में रहेगा और इसे इस तरह बनाया गया है कि यह खून की लगातार जांच कर रिपोर्ट देगा। आप जहां हैं, वहीं आप अपने खून की जांच कर सकते हैं। इसका रिजल्ट भी 3 से 5 मिनट के अंदर आपको मिल जाएगा। चूंकि जांच और रिजल्ट तत्काल मिल रहे हैं, लिहाजा बिना समय गंवाए संक्रमण फैलने से पहले ही वायरस जहां है, उसे वहीं उसे खत्म कर सकते हैं।

पेंटागन की सहयोगी पैथोलॉजी संस्था ने बनाई मशीन

इसके लिए पेंटागन की ही एक सहयोगी पैथोलॉजी संस्था के सहयोग से खून की जांच के लिए डायलिसिस की तरह एक मशीन विकसित की है। यह खून से वायरस को पूरी तरह से हटा देती है। डॉ. हेपबर्न ने बताया कि हमने एक सैन्यकर्मी 'पेशेंट-16' पर इसका प्रयोग किया। इस मशीन के जरिए उसके खून से वायरस को पूरी तरह खत्म कर दिया और वह अब तंदुरुस्त है। अमेरिकी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (एफडीए) ने इस मशीन को आपातकालीन उपयोग के लिए मंजूरी दे दी है।

आगामी आदेश तक बंद रहेंगे शासकीय एवं अशासकीय छात्रावास

सतना। स्कूल शिक्षा विभाग भोपाल द्वारा शासकीय एवं अशासकीय छात्रावासों को कोरोना कर्फ्यू (लॉकडाउन) के कारण आगामी आदेश तक बंद करने के आदेश जारी किये है। जारी आदेश के अनुसार कोविड-19 संक्रमण में हो रही लगातार वृद्धि के कारण कई जिलों में कोरोना कर्फ्यू (लॉकडाउन) की स्थिति है। समस्त शासकीय एवं अशासकीय छात्रावास तत्काल प्रभाव से बंद किए जाते है। छात्रावास में निवासरत समस्त विद्यार्थियों को सकुशल घर भिजवाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही बोर्ड परीक्षाएं संबंधित बोर्ड यथास्थिति माध्यमिक शिक्षा मंडल, सीबीएसई, आईसीएसई इत्यादि के निर्देश के अनुसार आयोजित होगी। इसी प्रकार शासकीय विद्यालयों में कक्षा 10वीं एवं 12वीं के छात्रावास के विद्यार्थी प्री-बोर्ड परीक्षा की अपनी उत्तर पुस्तिकाएं अपने घर की निकटस्थ शाला में जमा कर सकेंगे। उत्तर पुस्तकाओं के मूल्यांकन के संबंध में पूर्व में लोक शिक्षण संचालनालय से जारी निदेशों के अनुसार कार्यवाही की जाएगी।

दो हजार प्रोफसरों को दिया गया प्रशिक्षण

मप्र के 516 कॉलेजों में से 473 में प्रभारी प्राचार्य किया पदस्थ

स्टार समाचार | भोपाल

उच्च शिक्षा विभाग प्रोफेसरों की अंतिम वरिष्ठता सूची को जारी नहीं कर सकता है। इसमें जहां सीधी भर्ती और पदोन्नति ने मामला उलझा रखा है। वहीं आरक्षण का प्रतिशत फाइनल नहीं होने के कारण विभाग को प्रोफेसरों को प्राचार्य बनाने में काफी परेशानी आ रही है। इस कारण विभाग ने आरक्षण और वरिष्ठता को नजरअंदाज कर प्रशिक्षण प्राप्त प्रोफेसरों को प्राचार्य बनाएगा। इसके लिए करीब दो हजार प्रोफेसरों को प्रशिक्षण दिया गया है। विभाग प्रोफेसरों की अंतिम सूची करता है, तो प्रोफेसर हाईकोर्ट में सूची के खिलाफ याचिका दायर कर देते हैं। वहीं आरक्षण लागू करने का मामला सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों पर छोड़ रखा है।

इसके बाद भी शासन प्रोफेसरों को पदोन्नति देकर प्राचार्य बनाने की गुत्थी को नहीं सुलझा पा रहा है, इसलिए चयनित दो हजार प्रोफेसरों को प्रशासन अकादमी से ट्रेनिंग दी जा चुकी है। अब उन्हें प्राचार्य बनाया जाएगा। वर्तमान में प्रदेश के 516 यूजी-पीजी कालेज में से सिर्फ 43 प्राचार्य नियमित हैं। इसमें से तीन भोपाल में पदस्थ हैं, जिसमें स्टेट लॉ कालेज में सुधा बैसा और भेल कालेज में मथुरा प्रसाद पदस्थ हैं।

प्रभारी में हो रहे आए दिन विवाद

478 कालेजों में विभाग ने वरिष्ठ प्रोफेसर के अलावा जूनियर प्रोफेसर को प्रभारी प्राचार्य नियुक्त किया है। इससे कालेजों में आए दिन विवाद होते हैं। वहीं कई कालेजों में वरिष्ठ प्रोफेसर प्रभारी प्राचार्य रहना नहीं चाहते हैं, इसलिए विभाग को कई वरिष्ठ प्रोफेसरों ने प्रभारी प्राचार्य का पद छोड़ने के लिए आवेदन किए हैं।

ऑक्सीजन आपूर्ति के लिए एयर सेपरेशन यूनिट शीघ्रता से पूर्ण करें

भोपाल। लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव ने कहा है कि जिला चिकित्सालयों में ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए स्थापित किए जा रहे एयर सेपरेशन यूनिट की स्थापना का कार्य शीघ्रता से पूर्ण किया जाये। लोक निर्माण द्वारा प्रत्येक जिले में हॉस्टल, स्कूल, आश्रम, छात्रावास या अन्य भवनों में बनाए गये कोविड केयर सेंटर की व्यवस्थाओं की सतत निगरानी की जाये। उल्लेखनीय राज्य शासन द्वारा जिलों में ऑक्सीजन आपूर्ति तथा अस्थाई कोविड केयर सेंटर तैयार करने की जिम्मेदारी लोक निर्माण को सौंपी गई है। विभाग द्वारा इन केन्द्रों पर 10 हजार बिस्तर की व्यवस्था की गई है।

लॉकडाउन में दिव्यांग कर्मचारियों को उपस्थिति में छूट दें

रीवा। आयुक्त निःशक्तजन कल्याण संदीप रजक ने सभी संभाग आयुक्त और कलेक्टरों को जारी पत्र में कोरोना संक्रमण के कारण विभिन्न जिलों में लागू लॉकडाउन के दौरान दिव्यांग अधिकारियों और कर्मचारियों को कार्यालयीन उपस्थिति में छूट देने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि दिव्यांग जनों के संक्रमित होने का खतरा अधिक रहता है। इसलिए उन्हें विशेष कार्य होने पर ही कार्यालय बुलाया जाए और घर से ही कार्य करने की अनुमति दी जाए। कोरोना संक्रमण को केंद्र शासन द्वारा राष्ट्रीय आपदा घोषित किया गया है। कोरोना संक्रमण के मामले इन दिनों बहुत तेजी से देश प्रदेश में बढ़े हैं, हालांकि इनमें ठीक होने वाले लोगों की संख्या भी काफी बढ़ी है। दिव्यांग जनों की सुरक्षा और संरक्षण के मद्देनजर केंद्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग और मुख्य आयुक्त दिव्यांगजन द्वारा इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

जीएमसी में नर्सिंग स्टाफ, वार्ड बॉय को ऑक्सीजन बचाने की दी ट्रेनिंग

भोपाल। गांधी मेडिकल कॉलेज में हमीदिया अस्पताल के नर्सिंग स्टाफ, वार्ड बॉय, सफाईकर्मी एवं सुरक्षाकर्मियों को ऑक्सीजन के संबंध में जानकारी दी गई। इस दौरान प्रशिक्षणार्थियों को ऑक्सीजन के रेशनल उपयोग के संबंध में प्रशिक्षण दिया गया। इसमें बताया गया कि ऑक्सीजन के रेशनल उपयोग के बाद कोरोना पीड़ित ऑक्सीजन मास्क वाले मरीजों के खाना खाते समय, भ्रमण करते समय उनके बेड पर ऑक्सीजन सप्लाई बंद कर दी जाएगी।

प्रशिक्षण

आज का इतिहास

- **1841** : बॉम्बे गैजेट अखबार पहली बार रेशम के कपड़े पर प्रकाशित किया गया।
- **1920** : महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन का निधन।
- **1926** : जर्मनी और रूस ने शांति समझौते पर हस्ताक्षर किये।
- **1928** : मोम की मूर्तियों के लिये मशहूर 'मैडम तुसाद प्रदर्शनी' का लंदन में प्रदर्शन।
- **1942**: चीन में मंचूरिया के होन्केको में कोयला खदान में धमाके से 1,549 लोगों की मौत हुई।
- **1948**: बॉलीवुड अभिनेत्री मौसमी चटर्जी का जन्म।
- **1959** : क्यूबा ने पनामा पर आक्रमण किया।
- **1962** : पहली बार एक अमेरिकी अंतरिक्ष यान ने चाँद की सतह को छुआ।

आज का इतिहास

1864 पण्डित गुरुदत्त विद्यार्थी - स्वामी दयानन्द सरस्वती के शिष्य तथा आर्य समाज के पाँच प्रमुख नेताओं में से एक का जन्म हुआ।

1920 श्रीनिवास अयंगर रामानुजन, आधुनिक काल के एक महान भारतीय गणितज्ञ का निधन हुआ।

1987 शंकर- प्रसिद्ध संगीतकार (शंकर जयकिशन) का निधन हुआ।

2004 इराक के नये झंडे को मान्यता मिली।

2006 भारत और उजबेकिस्तान ने 6 समझौतों पर हस्ताक्षर किए।

2008 अमेरिका ने भारत के साथ किये गए 123 समझौते में किसी भी परिवर्तन की सम्भावना से इन्कार किया।

2010 बिहार सरकार ने बिहार के प्रसिद्ध चिनिया केले की ब्रांडिंग गंगा केला के रूप में करने का फैसला किया।